



मूल्यांकन की पद्धति

प्रिय अभ्यर्थियों,

आपकी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए परीक्षक-समूह के सदस्य निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान रखते हैं। आप भी इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि आप अपने प्राप्तांकों का तार्किक कारण समझ सकें।

परीक्षकों के लिये निर्देश

1. मूल्यांकन में अंकों का वही स्तर रखा जाना चाहिये जैसा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परीक्षकों द्वारा रखा जाता है।
2. सामान्य अध्ययन का जो उत्तर हर दृष्टिकोण से सटीक व उत्कृष्ट है; उसे अधिकतम 60% अंक दिये जाने चाहियें क्योंकि आयोग द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में भी इससे अधिक अंक मिलना लगभग असंभव है। वैकल्पिक विषयों के उत्कृष्ट उत्तरों तथा श्रेष्ठतम निबंधों में अधिकतम 70% तक अंक दिये जा सकते हैं।
3. कृपया अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार करें-

उत्तर का स्तर (Standard of Answer)	सामान्य अध्ययन में अंक-स्तर (Marks Standard G.S.)	वैकल्पिक विषय तथा निबंध में अंक-स्तर (Marks Standard - Optional Subject and Essay)
उत्कृष्ट (Excellent)	51-60%	61-70%
बहुत अच्छा (Very Good)	41-50%	51-60%
अच्छा (Good)	31-40%	41-50%
औसत (Average)	21-30%	31-40%
कमजोर (Poor)	0-20%	0-30%

4. कृपया उत्तर में निम्नलिखित गुणों को विशेष प्रोत्साहन दें-
 - प्रश्न की सटीक समझ व उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा
 - संक्षिप्त, टूट-टूट-पाईट लेखन शैली
 - प्रामाणिक तथ्यों का समुचित उपयोग
 - अधिकतम जरूरी बिंदुओं का समावेश
 - सरकारी दस्तावेजों (मंत्रालयों/आयोगों की रिपोर्ट्स, पॉलिसी पेपर्स आदि) के संदर्भों की चर्चा
 - प्रभावी भूमिका व निष्कर्ष
 - समकालीन घटनाओं/प्रसंगों को उत्तर से जोड़ना
 - दृष्टिकोण में संतुलन, समावेशन व गहराई
 - अच्छी, साफ-सुथरी हैंडराइटिंग
 - भाषा में प्रवाह
 - आवश्यकतानुसार डायग्राम्स, नक्शों आदि का प्रयोग
 - तकनीकी शब्दावली का सटीक उपयोग
 - सुंदर प्रस्तुति शैली (छोटे पैराग्राफ्स रखना, महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करना आदि)
 - विराम चिह्नों का समुचित प्रयोग
 - भाषा में वर्तनी व व्याकरण की शुद्धता
5. टॉपर्स के अनुभव बताते हैं कि उत्तर की विषयवस्तु अच्छी होने पर आयोग के परीक्षक शब्द-सीमा के थोड़े बहुत उल्लंघन पर अंक नहीं काटते हैं। कृपया आप भी इसी दृष्टिकोण के अनुसार अंक-निर्धारण करें।

Method of Evaluation

Dear Candidates,

While assessing your answer-scripts, the evaluators are required to follow the given instructions. You should also read them carefully to understand the logic behind the marks obtained by you in the tests.

Instructions for the Evaluators

1. The level of marks while evaluating the answers should be kept as per UPSC (Union Public Service Commission) standards as far as possible.
2. The answers of General Studies which are accurate and excellent from every perspective should be awarded a maximum of 60% marks as it is almost impossible to get more than that in actual UPSC examination. Excellent answers in optional subjects and the best written essays can be awarded a maximum of 70% marks.
3. Please assign the marks according to the following table-

4. Please devote special attention to the following qualities in an answer-
 - Accurate understanding of the question and systematic presentation of the answer
 - Crisp and to the point writing style
 - Adequate use of authentic facts
 - Inclusion of all the important points
 - Citing of relevant facts and figures from relevant official documents (Ministries /Commissions Reports, Policy Papers etc.)
 - Effective introduction and conclusion
 - Linking of current events and situations with the answer
 - Balance and depth in answer-writing
 - Legible and clean handwriting
 - Flow of language
 - Use of diagrams, maps etc
 - Precise use of technical terminology
 - Beautiful presentation style (small paragraphs, underlining important words etc.)
 - Proper use of punctuations
 - Correct spellings and right use of grammar
5. Experience of UPSC toppers also indicates that if the content of the answer is good, the UPSC examiners do not cut the marks on slight violations of the word-limit. Please award marks strictly according to the above-mentioned instructions.



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

1. सुस्पष्ट कीजिये कि उपनिवेशवाद ने किस प्रकार से औपनिवेशिक समाज को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया एवं उसे विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का अभिन्न अंग बना दिया? (150 शब्द) 10
Clarify how colonialism fundamentally changed the colonial societies and made them an inseparable part of the global capitalistic economy? (150 words) 10

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

~~उपनिवेशवाद के अभाव में ही~~
पुनर्जागरण से प्रेरित होकर यूरोपीय देशों ने व्यापार हेतु एशियाई, अफ्रीकन देशों के मध्य समुद्री यात्रा कर व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। मालों के आयात एवं व्यापार से उत्पन्न लाभ के लोभ ने इन साम्राज्यवादी ताकतों को उपनिवेश बनाकर शोषण करने को बाध्य किया।

शोषण के प्रथम चरण में ताकतों ने उपनिवेशों की राजनीतिक ताकतों पर अधिकार कर उनके राजस्व से ही व्यापार करना शुरू किया परंतु धीरे-धीरे औद्योगिक क्रांति के जलस्वरूप पश्चिम की भूमि मशीनों एवं कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए उपनिवेशों का सहारा लिया गया। यहाँ पर जबरन कच्चा माल उत्पादन कर निर्यात किया गया एवं वहाँ के तैयार माल के बाजार के लिए इन उपनिवेशों का प्रयोग किया गया। इससे अलावा उपनिवेशों के तैयार माल, हस्तशिल्प जो कि निर्यात किया जाता था पर जबरन अत्यधिक शुल्क लगाकर एवं आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाकर शुल्क कर दिया गया। इस प्रकार एकतरफा संरक्षण की नीति के कारण वहाँ उपनिवेश के कच्चे माल के स्रोत व तैयार माल के बाजार बन गए जबकि

1/4
वैश्व
प्रति उपनिवेश
काफ की
परिष्कारित
करें।



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

साम्राज्यवादी देश विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन।

इस प्रकार की व्यवस्था से उपनिवेशों की

मौलिक समाज संरचना टूट गई। हस्तशिल्प, बुनकरों

की कमाई टूट गई। वे रवि पर अनावश्यक बोझ

बन गए। सम्पूर्ण व्यवस्था चरमरा गई और

समाज उस पूंजीवादी अव्यवस्था के शोषित

वर्गों के रूप में उसका अंग बन गया।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

इसके अतिरिक्त कुछ न लिखें।
अच्छे से पढ़ें।
समाज के अंग बन गए।
सम्पूर्ण व्यवस्था चरमरा गई और समाज उस पूंजीवादी अव्यवस्था के शोषित वर्गों के रूप में उसका अंग बन गया।

कम-कम के अंग बन गए।
सम्पूर्ण व्यवस्था चरमरा गई और समाज उस पूंजीवादी अव्यवस्था के शोषित वर्गों के रूप में उसका अंग बन गया।

प्रधान अर्थ
व्य.
प्रगतिशील
और समाज
कार्य

3.5

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

2. उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विकासमान 'मध्यवर्गीय चेतना' जहाँ लोकप्रिय असंतोषों को संगठित कर राष्ट्रीय चेतना के विकास की महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई, वहीं वायसराय लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने इसे सशक्त बनाया। विवेचना करें। (150 शब्द) 10

The emerging 'middle class consciousness' in the late nineteenth century consolidated the popular unrest and proved to be an important factor in the development of national consciousness, while the reactionary policies of Viceroy Lytton strengthened it. Elucidate. (150 words) 10

वस्तुतः 1857 के संघर्ष के बाद से ही अंग्रेजों ने सामाजिक, राजनीतिक सुधार के झूठे दिखावे को त्याग कर प्रतिक्रियावादी रुख अपना लिया था। अंग्रेजी शिक्षा एवं भाष्यात्मक ज्ञान-विज्ञान एवं दर्शन का अध्ययन कर भारत का शिथिल मध्य वर्ग अंग्रेजों की नीतियों पर प्रश्न उठाने लगा था।

भारतीय मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों जैसे - दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, आदि ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। नौरोजी जी ने 'पुर्वी एंड अन्विक्रिशरुल इन इंडिया' जैसी पुस्तक लिखी थी जो बहिष्कार का सिद्धान्त दिया तथा 'ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', मद्रास महाजन समाज जैसे संगठनों ने राजनीतिक चेतना का संवनाद दिया।

वहीं दूसरी ओर वायसराय लिटन जैसे प्रतिक्रियावादियों ने बार्नामुलर प्रेस एक्ट (1878) जैसे कानूनों जिन्हें अन्तर्गत दिली भी अखबार को बंद किया जा सकता था, आर्म्स एक्ट (एचिभर रखने की अनुमति न देना) आदि के द्वारा इस राष्ट्रीय चेतना को खाने का भरपूर प्रयास किया परन्तु इस

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आरंभिक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों में भी प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने भाषणों, मंचों, सेमिनारों के माध्यम से इन नीतियों की चर्चा कर कड़ बलिचिना की। इस प्रकार लिखन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने राष्ट्रीय चेतना को स्वतंत्र ही किया।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

एक। धीरे धीरे
good

4.5

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

4. 'बाँटो और राज करो' की औपनिवेशिक नीति ने ही भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया जो कालांतर में वट वृक्ष बन गया और उसने भारत की सदियों पुरानी समरसता को भंग कर दिया, अंततः इसी की परिणति देश के विभाजन के रूप में परिलक्षित हुई। चर्चा करें। (150 शब्द) 10

It was the purposeful colonial policy of 'Divide and rule' that laid the seeds of communalism which grew into a huge tree that disturbed the solidarity of the age-old mosaic of India and inevitably led to its partition. Discuss. (150 words) 10

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप में सहिष्णु रही है। जो भी बाहरी आक्रमणकारी यहाँ आए, वे यहाँ के होकर रह गए। इस बात के उदाहरण उपलब्ध हैं कि अंग्रेजों के आक्रमण से पहले भारत में सांप्रदायिक आधार पर दंगे, लड़ाई, अशांति जैसी वस्तु विद्यमान नहीं थी।

अंग्रेजों की नीतियाँ धार्मिक आधार पर बाँटने की तर्ज पर परिवर्तनशील रही हैं। 1857 की क्रान्ति से पूर्व अंग्रेज मुस्लिम उन्मुख रहे और मुस्लिम जमींदारों, शासकों से सहयोग प्राप्त करते रहे परन्तु 1857 के विद्रोह में उन्होंने यह समझा कि हिंदू-मुस्लिम एकजुटता उन्हें शासन के स्थान पर खतरा है अतः उन्होंने 'फूट डालो राज करो' की नीति को अपनाते हुए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए हिंदू उद्दिष्टियों के पक्षधर रहे।

कालान्तर में हिंदू श्रमिक वर्ग द्वारा अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की आलोचना एवं स्वतंत्रता की मांग के कारण तेवर बदलते हुए अंग्रेजों में मुस्लिम संप्रदायवादी नेताओं के विद्रोह पर अपना दाय्य रखा एवं उन्हें समर्थन दिया। इसके अलावा बाद में

अंग्रेजों ने
लक्ष्य
किया

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

8. विश्लेषित कीजिये कि किस प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध 'रूसी क्रांति' के लिये एक ऐसी घटना सिद्ध हुई जिसने रूसी जनता को राजनीति से जोड़ा तथा एकतंत्रीय सत्ता के विरोध में सभी राजनीतिक ताकतों को एकसूत्र में पिरो दिया। (150 शब्द) 10

Analyze how the First World War proved to be an important factor in the 'Russian revolution' which linked Russian people to politics and united all the political forces in opposing autocratic power. (150 words) 10

रूस में निरंकुश राजतंत्र का शासन था जिसका प्रमुख कारण कहलाता था। यहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धान्तों की तरह शक्ति बहल समाज न होकर गरीब हल्का बहल समाज था। लगभग डेढ़ लाख अमीर सामंतों के पास देशकी 70 प्रतिशत भूमि थी जबकि 15 करोड़ गरीब किसानों के पास केवल 10 प्रतिशत। आर द्वारा संसद ड्यूमा में निरन्तर दस्तद्वेष, शक्तिशोका केन्द्रीकरण, अल्प औद्योगिकीकरण के कारण जो शक्ति आबादी थी वह भी अत्यन्त शोषित व उत्पीड़न युक्त जीवन जी रही थी।

इन सभी परिस्थितियों में आर द्वारा व्यापक विरोध के बावजूद सेना की प्रथम विश्वयुद्ध में लड़ाई दिया गया, जिसके फलस्वरूप देश के संसाधनों का दोहन हुआ, मंहगाई में वृद्धि हुई, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की भीषण कमी उत्पन्न हो गई। जनता में विद्रोह के स्वर बुलंद हो गए जिन्हें 'लेनिन' जैसे प्रखर नेता ने कु मजबूत आधार प्रदान किया। रूसी राष्ट्रवाद एवं शक्ति का अंश भी 1905 के जापान युद्ध में टूट चुका था। लेनिन के अ भीषण शोषणों, समानता के वादी एवं एक सुशासन समाज

यू.आर.के. (1905)

प्रश्नोत्तर
सुद्ध
आर्थिक
समाज-शासक
विद्रोह
सुशासन



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

इस सपने के कारण मार्क्सवाद के मजदूर वर्ग की जागृत मारीक किसान (कजुर दी गए एवं राजब्राही को उखाड केका। सेना ने भी विद्रोह का दमन करने से इंकार कर दिया। फलस्वरूप निरंकुश राजब्राही का अंत हुआ एवं विश्व का पहला समाजवादी देश स्थापित हुआ।

~~सूत्रागुलाह ~~सूत्रागुलाह~~ सुदुतीकरण को सुशानी कनात्रे।~~

2.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

13. सुस्पष्ट कीजिये कि हाल के वर्षों में संसदीय कार्यप्रणाली की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में किस प्रकार का क्षरण दृष्टिगत हो रहा है एवं इसके उपचार हेतु आप किस प्रकार के सुधारों की अनुशांसा करेंगे? (250 शब्द)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

Explain how the productivity and effectiveness of the Parliamentary system have witnessed degeneration in recent years and what recommendations would you give to arrest the malaise? (250 words)

'संसद' - एक ऐसा शब्द है जिसका नाम लेते ही हमारे जेहन में एक ओजस्वी कल्पनाओं का समूह आता है परन्तु दलिया वर्षों में संसद सदस्यों की स्थिति में बिगड़े उस कल्पना के समान हो गई है जिसे पूजा अर्चना से कोई मतलब नहीं, वह खड़ा होता है तो सिर्फ प्रसाद पाने के लिए। जाहिर है कि ज्यों-ज्यों भारतीय लोकतंत्र का विकास हो रहा है संसदीय गुणवत्ता एवं उत्पादकता का भरण हो रहा है -

सर्वप्रथम संसद के कार्यदिवसों की गणना करे तो 1950 से 60 के दशक तक औसतन संसद 140 दिन चलती थी जो दलिया वर्षों में केवल 70 दिन ही रह गई है।

- प्रति मिनट 2.5 लाख के खर्च से चलने वाली संसद का अधिकांश समय शोर शराबे और दंगलों में ही भेंट पड़ जाता है।

- लैंगिक समावेशन का अभाव अर्थात् मौजूदा संसद में केवल लगभग 11% महिलाएँ हैं और महिला आरक्षण विधेयक (108 वां संशोधन) अरसे से लॉकित है।

- संसद में बौद्धिक संपन्न निवेश का अभाव है तथा कानूनी अड-चनो एवं संविधान संशोधन विधेयकों की कमी के चलते कानूनों की न्यायिक समीक्षा के धैरे में आना पड़ता है।

- दल-बदल कानून के कारण संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की बजाय सिर्फ पार्टी रीखा पर ही चलते हैं।

→ प्रभावी
आवाजों की
लाभ
राष्ट्रीय
को देखें
(गर्भ)

गुणवत्ता

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस कुछ न लिखें।

(Please do not write anything in this space)

संसदी लाइब्रेरी एवं प्रलेखन, सूचना व संदर्भ विभाग में भी आवश्यक स्टाफ का अभाव है। इसके अलावा यदि अन्य देशों की संसदों से तुलना की जाये तो अमेरिकी कांग्रेस का एक वर्ष में 150 दिन विधि संसद 140 दिन चलती है एवं यहाँ के सांसदों को भी पार्टी लाइन से दूर भी मतदान की अनुमति है -

इस सभी समस्याओं के उपचार में निम्न समाधान सुझाए जा सकते हैं

(अ) संविधान की समीक्षा पर अखिलमण्डल द्वारा लोकसभा व राज्यसभा के कार्यदिवसों को नियत करने की सिफारिश को लागू करना जो क्रमशः 120 दिन व 100 दिन थी। ध्यातव्य है कि उद्देश्य राज्य द्वारा इस संदर्भ में एक बिल भी पारित किया गया है।

(ब) महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना।

(स) बौद्ध संघ में पर्याप्त निवेश करना।

(द) संसदीय मंत्रालय की सिकरिगानुसार अमेरिकी कांग्रेस की प्रथा को अपनाने हेतु एक अलग से समिति का गठन किया जाना चाहिए।

(ध) संसदीय समितियों की शक्ति को बढ़ाकर उन्हें कार्यकारी प्रभुत्व की जानी चाहिए।

(ण) निजी विधेयकों को भी पर्याप्त सम्मान देकर विचार दिया जाना चाहिए।

(त) दल-बदल कायून में उचित संशोधन देने चाहिए।

ध्यातव्य है कि उपर्युक्त संशोधनों को लागू करने से ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व के सबसे

संसदीय मंत्रालय की सिकरिगानुसार अमेरिकी कांग्रेस की प्रथा को अपनाने हेतु एक अलग से समिति का गठन किया जाना चाहिए।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

~~के परिपक्व लीकतंत्र का परिचायक बने सिद्धा और मंदिर के बालक की पूजा - अर्चना का महत्व व उसमें निहित आनंद को हम समझ आएगा।~~

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

पूजा अर्थात् पूजा
आकाश की पूजा
कला

6.5

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

15. केंद्र-राज्य विधायी संबंधों में क्षेत्रीय न्यायक्षेत्र के मामले में संसद पर किस प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किये गए हैं? साथ ही स्पष्ट करें कि किन असामान्य स्थितियों में राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान बनाए जा सकते हैं? (250 शब्द)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

In the context of regional jurisdiction in centre-state legislative relations, what restrictions have been imposed over Parliament? Also explain under which exceptional circumstances Parliament can make laws on subjects in state list. (250 words)

संविधान के अनुच्छेद -1 के अनुसार भारत-राज्यों का संघ है। भारत में संघात्मक पद्धति को अपनाया गया है जो फ़ेडरल मॉडल पर आधारित है अर्थात् 'द्विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ' है। संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची व सम्मती सूची का प्रबन्ध है जिसके अनुसार केंद्र व राज्य की विधाधिकारें अपनी-अपनी सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है एवं सम्मती सूची पर दोनों कानून बना सकती हैं, हालांकि संसदीय कानून विवाद होने की स्थिति में प्रभावी होगा। इससे अलावा क्षेत्रीय न्यायक्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ विधेय हैं-

- (i) संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती है।
- (ii) सम्मती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए।
- (iii) ऐसे संविधान संशोधन जिनसे संविधान की संघात्मक प्रकृति में परिवर्तन होता है, करने के लिए आठ राज्यों की मंजूरी आवश्यक है (अनुच्छेद 368)
- (iv) नए राज्यों के निर्माण हेतु पुराने राज्यों की विधायकसभा से सिकांतिश लेनी चाहिए हालांकि इन सिकांतिशों को मानने हेतु संसद बाध्य नहीं है।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस कुछ न लिखें।
(Please do not write anything in this space)

इसके अलावा कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।

(क) अपातधान के समय (अनु. 352) - राष्ट्रीय आपत के समय राज्य विधायिकाएँ विधायित्व नहीं होती हैं फिर भी संसद कानून बना सकती है।

(ख) राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) के दौरान - विधानसभा निलंबित या विघटित हो जाती है। कानून तब तक प्रभावी रहता है जब तक नव विधानसभा उसे संशोधित या स्थगित न कर दे।

(ग) जब दो या दो से अधिक राज्य संकल्प पारित कर यह प्रस्ताव करें कि अमुक विषय पर संघीय कानून बनाना चाहिए तब परन्तु फिर भी राष्ट्रपति वापिस राज्य विधानसभा को शक्त नहीं होती है।

(घ) प्राकृतिक आपदा के अन्तर्द्वेष 249 के तहत संकल्प पारित कर यह सिद्ध करें कि अमुक महत्व के मुद्दे पर संसद को कानून बनाना चाहिए तब संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना लेगी। ऐसे कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहते हैं।

इस प्रकार भारतीय शासन पद्धति वर्णित संघात्मक नहीं है। परिस्थितियाँ अनुसार इसमें स्वात्मकता या शक्ति हस्तांतर के कारण नज़र आते हैं जिन्हें

अधुनिक परिस्थितियों के आधार पर समझा जा सकता है।

संघीयता

Group

7

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

16. नीति आयोग ने किन कारणों से अपने तीन वर्षीय कार्यवाही एजेंडे में कृषिगत आय की एक निश्चित सीमा पर करारोपण का प्रस्ताव किया है? इसका अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (250 शब्द) 15

Explain the reasons behind proposed taxation over a certain threshold of agriculture income in its 3 year action plan by NITI Aayog. What will be its impact on economy and society? (250 words) 15

हाल ही में नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था को खत्म कर तीन वर्षीय कार्यवाही एजेंडा आदि का सुनपात किया गया है। गौरवपूर्ण है कि नीति आयोग द्वारा देश की के आय पर में वृद्धि हेतु एक निश्चित सीमा तक करारोपण का सुझाव दिया है जो अमीर एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ किसानों पर लगाया जाएगा। इसके प्रभाव निम्न हो सकते हैं -

(क) अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

सरकारत्मक प्रभाव -

- (i) देश की राजस्व आमदनी में वृद्धि होगी।
- (ii) कर आधार विस्तृत होगा एवं अधिक प्रत्यक्ष कर से अधिक प्रत्यक्षता का सिद्धान्त मजबूत होगा।
- (iii) आर्थिक रूप से मजबूत किसानों पर कर लगाकर उनकी अनिश्चित आय का प्रयोग लोक-कल्याणकारी नीतियों में किया जा सकेगा।

नकारात्मक प्रभाव -

- (i) रुषि का पिछापन आज की सबसे बड़ी समस्या है और अनिश्चित कर लगाकर इसके और अधिक विकृत होने की संभावना है।
- (ii) जहाँ आज किसानों की उत्पादकता, उचित मूल्य न मिल पाने, फलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से

दिव्य में वृद्धि आत्र कर लगावे प्रत्यक्ष कर नीति आयोग के तर्क को स्पष्ट करे

Good

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

लड़ना पड़ रहा है वही अतिरिक्त करारोपण स्थितियाँ बढ़ते वना सकता है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

(ख) समाज पर प्रभाव

• सकारात्मक :- (i) समाज की आर्थिक विषमता कम करने में मदद मिलेगी। अमीर किसानों की आय को एक अलग फंड बनाकर गरीब किसानों के उन्नयन में प्रयोग किया जा सकता है।

(ii) कुछ शक्तिशाली नेता या व्यक्तियों द्वारा अपनी आय को हथिगत क्लार जो कर-चोरी की जाती है उसे रोका जा सकता है।

good

• नकारात्मक प्रभाव :- (i) अमीर किसानों मिलीभगत से कर चोरी कर सकते हैं परन्तु मध्यम वर्ग के किसान अपनी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही गरीब किसानों की सामाजिक उन्नयन की गति प्रभावित हो सकती है।

हालांकि कुछ चुनौतियाँ जैसे- राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रस्तावों की पहचान की समस्या, उचित टैक्स दर की समस्या, अमीर आपदा आ जाए तो क्राधान किस प्रकार होगा; आर्थिक सम्पन्नता का पैमाना क्या है? आदि कुछ ऐसे खवाल हैं जिन पर विचार किया जाना

good

आवश्यक है यह एक विवक्ति मुद्दा है जिस पर उचित विचार विमर्श पर गरीब किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही इस पर कार्य करना चाहिए।

कारण :- (i) अमीर एवं सुदृढ किसानों द्वारा कर में

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

दूर का लाभ उठाना

- (ii) आर्थिक विषमता - गरीब व अमीर किसानों में दृष्टि प्राणिकीय प्रत्यक्ष आधारित व्यवस्था से इसे दूर करने की इच्छा
- (iii) राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा कृषि आधारित बतौर दूर दूर का लाभ उठाना।
- (iv) आधार को विस्तृत बनाने की अकांक्षा।

कृषि आधारित

प्रमाण आधारित

6.75

कृपया इस

कुछ न लिखें।

(Please do not write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

18. भारत के सभी परिवारों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक ऐसे ऊर्जा ढाँचे की आवश्यकता है जो इकित्ती, दक्षता एवं स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित हो। सरकार द्वारा शुरू की गई 'सौभाग्य योजना' के संदर्भ में उक्त कथन पर प्रकाश डालें। (250 शब्द) 15

To make electricity available to every household in India, a power distribution structure is needed which is based on equity, efficiency and sustainability. Explain the above statement in the context of the 'Saubhagya Yojana' started by the government. (250 words) 15

पिछले वर्ष के मध्य में प्रधानमंत्री द्वारा 'बी.पी.एल परिवारों' के न लिए बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री सार्वजनिक बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का लुप्तप्राय प्रिय जिसके अन्तर्गत 16,000 करोड़ की लागत से देश के 4 करोड़ बी.पी.एल परिवारों को मुक्त कनेक्शन प्रदान किए जायेंगे।

इतनी बृहद परिचयोजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त, प्रशासनिक सक्रियता के अन्वय सबसे बड़ी जरूरत ऊर्जा ढाँचे की है। न केवल बिजली का उत्पादन बल्कि बिजली उत्पादन, परिष्कार में इकित्ती, दक्षता एवं स्थिरता भी अत्यावश्यक है। इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है-

(i) भारत में बिजली में गिरावट की समस्याएँ विद्यमान हैं जिसके कारण बिजली का अपत्यय स्थानान्तरण के दौरान ही हो जाता है

(ii) ऊर्जा उत्पादन की परिचयोजनाओं में देरी की भी समस्या है, भव्यपि भारत विश्व में एक बड़ा नव्यकरणीय ऊर्जा हेतु प्रोजेक्ट (2022 तक 100 गीगावाट) चला रहा है परन्तु इस उत्पादित बिजली को उपयुक्त रूप से समाभोगित व स्थानान्तरित करने की

आन्धी सुलभात

कृपया इस कुछ न लिखें। (Please do not write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

आवश्यकता है।

(iii) प्रायः देखा जाता है कि कर्जा राज्य केवल उन्हीं राज्यों में विकसित है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं एवं लरीज हैं। पिछड़े, उरीब एवं पहाड़ी राज्यों में भी बिजली के स्थानान्तरण हेतु सरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।

(iv) जहाँ तक दसत) का सवाल है विभिन्न सौर रूक टॉप, ग्रीन बिल्डिंग, पवन ऊर्जा यन्त्रियाँ, पम्प मशीनें आदि का प्रयोग, जागरूकता केलाकर बिजली की बचत की जा सकती है। इस अतिशेष बिजली का स्थानान्तरण पिछड़े वर्गों में किया जा सकता है।

ऐसा भी नहीं है कि सरकार द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा सौर पार्क, पहाड़ी क्षेत्रों में लघु पनबिजली परियोजनाओं, पवन ऊर्जा में पर्याप्त निवेश किया जा रहा है जो कि बिजली आपूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। दसत) के स्तर पर ग्रीन बिल्डिंग, जैसी अवधारणाएँ विद्यमान हैं तो चारेखण की समस्या के लिए विभिन्न राज्यों एवं केंद्र के सहयोग से गतिशील का निर्माण किया जा रहा है जो कि इस समस्या के समाधान में सहायक होगा।

इस प्रकार बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। जैसी कक्षावर्तों के परिचित जागरूकता केलाकर ही बिजली के आधिक्य को सौभाग्य जैसी योजनाओं के द्वारा पिछड़े व उरीब वर्गों के घर में रोशनी देने हेतु किया जा सकता है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

सराधीन
पुत्रा ल

good

7.5

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

(अ) क्राधान संबंधी मुद्दे :- भारत में कानून है कि भारत कंपनियों के निवेश के संग्रह डर कर समझौतों में संशोधन कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियां इसे बुरा आतक्वाफरी संख्या देती हैं।

निवेश के समाधान :-

(क) आधारभूत ढांचे में निवेश करना - इस हेतु सरकार द्वारा भारतमाला, सागरमाला, तटीय आर्थिक क्षेत्र आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं जिन्हें त्वरित किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करना। सरकार प्रधानमंत्री कृषि संवर्धन योजना, मेगा फूड पार्क एवं विश्व खाद्य भारत जैसे अभियानों द्वारा इसे बढ़ावा दे सक रही हैं।

(ग) कृषि आधुनिक सुनिश्चित करना - सरकार द्वारा नवकरबीज कृषि हेतु एक व्यापक (100 Cr) का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे अलावा सरकार की परीक्षण लॉब्स में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(घ) कुशलश्रमिकों की आधुनिक करना - स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को त्वरित कर समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

(ङ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास जो कि भारत के निर्माण क्षेत्र में 40 कीसदी योगदान देते हैं।

इससे अलावा सरकार की उपभुक्त उपायों के अलावा नीतियां एवं क्रियान्वयन के स्तर पर सुसंशोधन सुधार कर, कर प्रावधानों को सरल बनाने

दुर्लभ

सरकार का प्रबल प्रावधानों का सुसाध है



कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

~~का प्रवास करना चाहिए ताकि अन्तर्राष्ट्र पर
चीन के संसद मंद्गी होते श्राम के कारण वैदराष्ट्रीय
कंपनियों के भारत आगमन एवं जनानांशिय लाभों
से देश का विकास सुनिश्चित किया जा सके।~~

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

~~वेदल प्रभाव है~~
~~Good~~

7.5

Feedback

Questions
Model Answer & Answer Structure
Evaluation
Staff



641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: [facebook.com/drishtithevisionfoundation](https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation), ट्विटर: twitter.com/drishtiiias



रफ़ कार्य के लिये स्थान
(Space for Rough Work)



प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

समग्र मूल्यांकन

(Overall Evaluation)

- अच्छा प्रयास है।
- सभी अनिवार्य प्रश्नों का उत्तर देना।
- प्रस्तुतिकरण पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- निरंतर उत्तर लेखन का आग्रह करें।